गुरुवार, 30 जुलाई,2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

शुभमन गिल ने एक बार फिर नंबर-1 बल्लेबाज का ताज हासिल कर लिया

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

67 साल के हुए संजय दत्त: संघर्ष, विवाद और शानदार वापसी से बने बॉलीवुड के 'बाबा'

Page-05

सत्ता पक्ष-विपक्ष में तीखी बहस

लोकसभा से पास हुआ परीक्षा में नकल रोकने वाला संशोधन विधेयक

- पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 ध्वनिमत से लोकसभा में पारित हो गया।
- जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी और विपक्ष पर विधेयक का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि संसद में तथ्यों व मर्यादा के साथ चर्चा होनी चाहिए थी।

लोकसभा ने पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 को बुधवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देने के बाद इसे संशोधनों सहित सदन से मंजूरी मिली। अब यह विधेयक आगे की प्रक्रिया के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा।विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर इस महत्वपूर्ण विषय का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े इस विधेयक पर रचनात्मक सुझाव देने के बजाय विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया।डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संसद में इस्तेमाल की गई भाषा संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं थी। मंत्री ने कहा कि देश के युवाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे गलत संदेश जाता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या विपक्ष के नेता संसदीय कार्यवाही के मूल नियमों से पूरी तरह परिचित हैं। उनके अनुसार संसद में चर्चा तथ्यों, तर्कों और मर्यादा के साथ होनी चाहिए।राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने 21 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए धरने का भी जिक्र किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो राहुल गांधी की इच्छा 7, लोक कल्याण मार्ग तक पहुंचने की थी और जब ऐसा नहीं हो सका तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया।कई घंटे चली चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब दिया। इसके पश्चात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित होने की घोषणा की। विधेयक पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अंतिम मंजूरी के लिए राज्यसभा में चर्चा होगी।

राहुल गांधी का आजपा पर हमला

'माइक बंद कर सकते हैं, छात्रों की आवाज नहीं

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा पर संसद में अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाया है। सदन की कार्यवाही के बाद मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि जब वह छात्रों से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे, तब भाजपा सांसदों ने उन्हें बोलने नहीं दिया और उनका माइक भी बंद कर दिया गया।राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि वह बुधवार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा कि संसद में जो बातें उन्हें कहने की अनुमति नहीं मिली, उन्हें वह मीडिया के सामने विस्तार से रखेंगे। अपने पोस्ट में राहुल ने लिखा कि उन्होंने सदन में दिल्ली में छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया, लेकिन उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी गई।राहुल गांधी ने कहा, "भाजपा मेरा माइक बंद कर सकती है, लेकिन छात्रों की आवाज को नहीं दबा सकती।" उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।राहुल गांधी का यह बयान 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के संदर्भ में आया है। उस दिन नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई हुई, जिसमें कई छात्रों के घायल होने का दावा किया गया। राहुल गांधी ने इस घटना को गंभीर बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

BJP का राहुल गांधी पर पलटवार

संबित पात्रा बोले- छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष ने की राजनीति

लोकसभा से एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक, 2026 पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि विपक्ष ने पूरे मानसून सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही बाधित की और महत्वपूर्ण विधेयकों पर रचनात्मक चर्चा करने के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को प्राथमिकता दी।संबित पात्रा ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों और विभिन्न पक्षों से व्यापक संवाद किया। इसके बाद कानून को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन किए गए, ताकि भविष्य में सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नया संशोधित कानून करोड़ों छात्रों के हितों की रक्षा करेगा और परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष ने इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक सुझाव देने के बजाय सदन में लगातार हंगामा किया। राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने सदन में तथ्यात्मक रूप से गलत बातें रखीं और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण में कई विरोधाभास थे और उनके आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं थे। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह छात्रों के भविष्य जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाए।

जांच में नहीं मिली कोई खामी

बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के फ्यूल सिस्टम पर सरकार की सफाई

बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के फ्यूल सिस्टम को लेकर उठी सुरक्षा चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने राहत भरी जानकारी दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने संसद में बताया कि फरवरी 2026 में लंदन से बेंगलुरु आ रही एयर इंडिया की बोइंग 787 उड़ान में पायलटों द्वारा फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की आशंका जताई गई थी। हालांकि, बोइंग की विस्तृत जांच में इस स्विच में किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी नहीं मिली है।यह घटना उस समय सामने आई थी जब उड़ान के दौरान पायलटों को फ्यूल कंट्रोल स्विच के कामकाज को लेकर संदेह हुआ। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उन्होंने इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी। विमान सुरक्षित रूप से बेंगलुरु में उतरा, लेकिन घटना के बाद फ्यूल कंट्रोल सिस्टम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठने लगे। इसके बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बोइंग कंपनी से विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए।संसद में लिखित जवाब देते हुए मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि जांच के दौरान फ्यूल कंट्रोल स्विच में किसी प्रकार की असामान्यता नहीं पाई गई। हालांकि, एहतियात के तौर पर विमान के थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल की विस्तृत तकनीकी जांच अभी भी बोइंग की विशेष सुविधा में जारी है। उन्होंने कहा कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।सरकार ने दोहराया कि विमानन सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तकनीकी संकेत को हल्के में नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक रिपोर्ट की गहन जांच की जा रही है ताकि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। गौरतलब है कि जून 2025 में गुजरात में एयर इंडिया के एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 260 लोगों की मौत हुई थी। उस हादसे के बाद बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल सिस्टम और इंजन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण उपकरणों की निगरानी और जांच को और सख्त कर दिया गया है।

CJI को गाली देने वाले को जमानत

सुप्रीम कोर्ट में हंगामा काटने, पेपर उछालने और यहां तक कि भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) को भद्दी गालियां देने वाले शख्स को दिल्ली की एक निचली अदालत से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट और अदालत की कार्यवाही बाधित करने के आरोपों में दो लॉ स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सीजेआई को अपशब्द बोलने वाला वह व्यक्ति भी शामिल है। दोनों आरोपियों को बेल देते हुए निचली अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था की गरिमा किसी एक परेशान और बिना वकील वाले याचिकाकर्ता के बेलगाम बर्ताव से कमतर नहीं हो सकती, इसलिए निचली अदालतों को भी संस्थागत संयम का पालन करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोर्टरूम का जो वीडियो आया था, उसमें वह सीजेआई के लिए भद्दी गालियां निकाल रहा था।

बैरिकेड्स तोड़े, CM हाउस घेरने की चेतावनी

MSP और खाद वितरण को लेकर भोपाल में किसानों का हंगामा

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। मूंग की फसल की 100 प्रतिशत खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित करने और खाद वितरण में लागू टोकन प्रणाली समाप्त करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भोपाल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। आंदोलन के कारण बुधवार को होशंगाबाद रोड और आसपास के क्षेत्रों में लंबा जाम लगा, जिसके चलते एहतियात के तौर पर कई निजी और सरकारी स्कूलों ने अवकाश घोषित कर दिया।प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर किसानों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। नर्मदापुरम क्षेत्र में किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और कुछ प्रदर्शनकारी बसों पर चढ़ गए। किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया। आंदोलन के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि यह आंदोलन अभी सिर्फ शुरुआत है।किसान संगठनों का कहना है कि सरकार को उनकी मांगों पर दोपहर 2 बजे तक फैसला लेना होगा। यदि तय समय तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो हजारों किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। किसान स्वराज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और मूंग की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का तत्काल निर्णय लेना चाहिए।आंदोलन के दौरान किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना की "सद्बुद्धि" के लिए यज्ञ भी किया। किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अब सभी की नजर सरकार और किसान संगठनों के बीच संभावित बातचीत तथा उसके नतीजों पर टिकी हुई है।

पीओके में हिंसा की आग: प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी, 40 मौतों का दावा

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के बीच हिंसा तेज हो गई है। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल और कई गिरफ्तार किए गए हैं। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं से तत्काल हस्तक्षेप तथा स्वतंत्र जांच की मांग की है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बुनियादी जरूरतों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी फौज ने बंदूक का इस्तेमाल किया। पाक फौज की कार्रवाई में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों से अधिक लोग घायल हैं। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने बुधवार को रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि 27 और 28 जुलाई के बीच रावलाकोट, मीरपुर और अन्य क्षेत्रों में करीब 40 नागरिकों की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल हुए और मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए गए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने कहा कि 5 जून से अबतक POJK (आजाद कश्मीर) में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सैकड़ों घायल हुए और सैकड़ों लोगों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर जबरन लापता किया गया है। यूकेपीएनपी ने पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ अत्यधिक या गैरकानूनी बल का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन है और यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकता है। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपी संघ और अंतरराष्ट्री मानवाधिकार संगठन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उधर, पीओजेके की ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अम्मान खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी बलों ने पिछले दो दिनों में दर्जनों प्रदर्शनकारियों की बेरहमी से हत्या की। सरदार अम्मान खान ने पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई को निहत्थे नागरिकों का नरसंहार करार दिया। अम्मान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सिर्फ दो दिनों में पाकिस्तानी बलों ने 38 शांतिपूर्ण कश्मीरी प्रदर्शनकारियों की बेरहमी से हत्या कर दी। यह कानून लागू करना नहीं, बल्कि अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे निहत्थे नागरिकों का नरसंहार है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीओके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तानी प्रशासन शांतिपूर्ण आवाजों का जवाब घातक बल प्रयोग से दे रहा है। अम्मान खान ने हिंसा तत्काल रोकने, मृतकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और घटनाओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों की मौत पर दुनिया चुप नहीं रह सकती। पीओजेके में जारी ये प्रदर्शन इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे नियंत्रण को खुली चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं। आरोप है कि इसके जवाब में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने व्यापक दमन अभियान चलाया है, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई हैं, कई घायल हुए हैं और बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का दौर जारी है। पूरे क्षेत्र में कई दिनों से कड़ी नाकेबंदी, कर्फ्यू और संचार सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है।

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच रुक-रुककर जंग जारी

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच रुक-रुककर जंग जारी है। बीते हफ्ते तक ईरान पर लगातार हमले के बाद अमेरिका ने अपने हमले रोक दिए थे। इसके बाद ईरान ने भी हमलों की रफ्तार रोक दी। माना जा रहा था कि दोनों देश एक बार फिर से बातचीत की मेज पर वापस आ सकते हैं। हालांकि, अब अमेरिकी सेंट्रल कमान (CENTCOM) ने जानकारी के दी है कि ईरान ने अचानक से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर से जंग शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी सेंट्रल कमान अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर के ईरान के मिसाइल हमले के बारे में जानकारी दी है। CENTCOM ने बताया- "आज शाम 5:45 बजे (ET), इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सेनाओं ने ईरान से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। यह मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना पर अचानक हमला करने की कोशिश थी। ईरान की सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। अमेरिकी सेना सतर्क है और पूरी तरह तैयार है।" अमेरिका और ईरान के बीच कुछ समय से शांति थी। दोनों ही देशों ने कुछ दिनों से एक दूसरे के खिलाफ किसी भी हमले की घोषणा नहीं की थी। इससे पहले कई हफ्ते तक दोनों देशों के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव जारी था। आपको बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में ये समुद्री रास्ता दुनिया भर के लिए काफी अहम बन चुका है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के दौरान होर्मुज स्ट्रेट की रास्ते न के बराबर ऊर्जी की सप्लाई हो रही थी।

ऑटोमोबाइल निर्माताओं पर कथित तौर पर 'दबाव' डालने का आरोप

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर ऑटोमोबाइल निर्माताओं पर कथित तौर पर 'दबाव' डालने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह दबाव E20 पेट्रोल के साथ वाहनों की अनुकूलता (compatibility) को लेकर है। केजरीवाल ने चिंता जताई कि 2023 से पहले निर्मित वाहन E20 पेट्रोल के उपयोग से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और उनके प्रदर्शन में समस्या आ सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ऑटोमोबाइल कंपनियों पर दबाव बना रही है कि वे यह साबित करें कि उनके वाहन E20 पेट्रोल के अनुकूल हैं। केजरीवाल के अनुसार, यदि वाहन निर्माता इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, तो सरकार उन्हें नए नियम लागू करने के लिए मजबूर कर सकती है। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि यदि पुराने वाहन E20 पेट्रोल का उपयोग करते हैं, तो उन्हें नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा ने प्रमुख उद्योगपतियों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है। पार्टी ने बताया कि व्यापक परीक्षण और सत्यापन के बाद यह पुष्टि की गई है कि E20 पेट्रोल वाहनों के लिए हानिकारक नहीं है। भाजपा ने इस बात पर जोर दिया कि ऑटोमोटिव सेक्टर E20 पहल का समर्थन करता है और केजरीवाल के आरोप निराधार हैं। E20 पेट्रोल, पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन का मिश्रण है। भारत सरकार पर्यावरण को बेहतर बनाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। इस पहल के तहत, 1 अप्रैल 2023 से देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री शुरू कर दी गई है।

रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर अब समुद्र में साफ दिखाई दे रहा

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर अब समुद्र में साफ दिखाई दे रहा है। ब्लैक सी के इलाके में बढ़ते हमलों ने समुद्र में चल रहे व्यापारिक जहाजों और उन पर काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी बात इस युद्ध क्षेत्र के करीब एक बंदरगाह पर भारतीय नाविकों की जिंदगी खतरे में है। जहां हर पल ड्रोन और मिसाइल हमलों का डर बना हुआ है। दरअसल यूक्रेन के चोरनामस्क बंदरगाह पर मालवाहक जहाज एमवी आमिर वन फंसा हुआ है। इस जहाज पर कुल 15 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। जिनमें 13 भारतीय नाविक शामिल हैं। नाविक संगठन फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया एफएसयूआई ने इस मामले को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि जहाज के आसपास लगातार हमलों का खतरा बना हुआ है। एफएसयूआई के मुताबिक जहाज पर मौजूद चालक दल बेहद तनावपूर्ण हालात में रह रहा है। संगठन ने दावा किया कि बंदरगाह के आसपास बार-बार ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश हो रही है। जिससे किसी भी समय जहाज को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है। नाविक संगठन ने भारत सरकार और संबंधित अधिकारियों से तुरंत कदम उठाने की अपील की। संगठन का कहना है कि युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाना चाहिए। एफएसयूआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें जहाज के आसपास धुएं के बड़े गुबार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में ब्लैक सी का इलाका लगातार खतरों से भरा हुआ है। यहां पहले भी कई बार व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और हमलों के कारण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां और समुद्री कर्मचारियों के लिए खतरा बढ़ गया। हाल के दिनों में भी ब्लैक सी क्षेत्र में व्यापारी जहाजों पर हुए हमलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले भी कई जहाजों को ड्रोन हमलों और सैन्य गतिविधियों के कारण नुकसान का सामना करना पड़ा है।

पटाया में बंधक बने तीन भारतीय रेस्क्यू, सस्ते टूर पैकेज के नाम पर रची गई साजिश

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

थाईलैंड में छुट्टी मनाने गए तीन भारतीयों के लिए यह ट्रिप एक बुरे सपने में बदल गई। उन्हें पटाया में भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों के एक गिरोह ने कथित तौर पर कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इन नागरिकों को स्थानीय पुलिस ने आखिरकार सोमवार को रेस्क्यू किया है। इन लोगों को किडनैप करने से पहले कम कीमत वाले टूर पैकेज का लालच देकर देश बुलाया गया था। इसके बाद इनको बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। थाईलैंड के अखबार बैंकाक पोस्ट के अनुसार, गिरोह ने पीड़ितों को बार-बार परेशान किया और उनके परिवारों से फिरौती मांगी। इनमें से पांच अपहरणकर्ताओं को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वे थाईलैंड से बाहर जाने के लिए फ्लाइट ले रहे थे। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी भारतीय नागरिक हैं। संदिग्ध पाकिस्तानी को अभी पकड़ा नहीं जा सका है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अवतार सिंह, जगजीत सिंह, रामबालक कुमार, सुखबीर सिंह और कुलरा सिंह के तौर पर हुई है। उन्हें बैंकाक के ख्लोंग टैन इलाके के एक होटल से पकड़ा गया। इनकी पकड़ से 23 से 26 साल की उम्र के इन तीन पीड़ितों को थाई पुलिस ने 27 जुलाई (सोमवार) को पटाया के बैंग लमुंग जिले में एक दो मंजिला घर से बचाया। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं का पता लगाकर इस जगह तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। गिरोह ने कथित तौर पर इन लोगों को कम कीमत वाले सात दिन के टूर पैकेज का लालच देकर थाईलैंड बुलाया था और फिर उनका अपहरण कर लिया था। उन्होंने कुल मिलाकर 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। सोमवार को पुलिस ने पटाया में छापा मारा तो उन्हें तीन लोग दो बेडरूम में बंधे हुए मिले। उनके हाथ, मुंह और पैर बंधे हुए थे। अधिकारियों ने उनके टखनों पर चोट के निशान भी देखे, जो कठोर चीजों से बार-बार पीटे जाने के कारण बने थे। सभी को अस्पताल ले जाया गया और जरूरी इलाज कराया गया। इन लोगों ने जांचकर्ताओं को बताया कि एक हफ्ते तक बंधक बनाए जाने के दौरान उन्हें रोजाना टॉर्चर किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उल्टा लटकाया गया, टखनों पर पीटा गया, खाना और टॉयलेट की सुविधा नहीं दी गई, और फिरौती की मांग के लिए भारत में अपने परिवारों को फोन करने के लिए मजबूर किया गया।

संपादक की कलम से

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से जुड़े तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था और जांच प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि यह फैसला उस समय आया है जब डॉ. मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इससे यह सिद्धांत मजबूत हुआ है कि केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जब तक उसके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद न हों।कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा। इस प्रकरण ने तत्कालीन सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए और राजनीतिक बहस को लंबे समय तक प्रभावित किया। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अभियोजन योग्य साक्ष्य न मिलने की बात कही थी, लेकिन विशेष अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर समन जारी कर दिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाई और अब अंतिम रूप से उसे निरस्त कर दिया है।यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में जांच एजेंसियों की भूमिका और अदालतों के अधिकारों के बीच संतुलन की भी याद दिलाता है। अदालतों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने का आधार केवल संदेह नहीं, बल्कि पर्याप्त और ठोस साक्ष्य होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इसी संवैधानिक सिद्धांत को दोहराता है।साथ ही यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था में लंबित मामलों की गंभीर समस्या को भी उजागर करता है। जिस अपील का अंतिम निपटारा एक दशक से अधिक समय बाद हुआ, उसका लाभ संबंधित व्यक्ति अपने जीवनकाल में नहीं उठा सके। न्याय में अत्यधिक देरी कई बार न्याय के वास्तविक उद्देश्य को कमजोर कर देती है। इसलिए आवश्यक है कि सार्वजनिक महत्व और उच्च पदों से जुड़े मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो।

CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर मनमोहन सिंह को मिली बड़ी राहत

यह मामला कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा है। उस समय डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं। अपीलकर्ता के निधन के कारण यह अपील निष्फल मानकर समाप्त की जाती है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित कथित कोयला घोटाले में उनके खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। इसके साथ ही इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पूरी तरह समाप्त हो गई। यह फैसला डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के करीब दो साल बाद आया है। उनका 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली के एम्स में निधन हुआ था।vयह मामला कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा है। उस समय डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। आरोप था कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को कोयला ब्लॉक आवंटित करने में अनियमितताएं हुई थीं। मामले की जांच सीबीआई ने की थी, लेकिन जांच एजेंसी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा था कि अभियोजन चलाने लायक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने क्लोजर रिपोर्ट नकारते हुए सिंह सहित छह आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी और धारा 409 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कथित अपराधों के लिए आरोपी के रूप में तलब किया। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पीएमओ के कुछ तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ करे। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद मार्च 2015 में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने यह कहते हुए कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर तलब किया था कि मामले में प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य आधार मौजूद हैं। इसके साथ ही अदालत ने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पी.सी. पारेख और तीन अन्य आरोपियों को भी समन जारी किया था। ट्रायल कोर्ट के आदेश को डॉ. मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि जब जांच एजेंसी ने किसी भी अभियोजन योग्य अपराध का मामला नहीं पाया, तब ट्रायल कोर्ट द्वारा समन जारी करना कानून के अनुरूप नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2015 में समन आदेश पर रोक लगा दी थी, जिससे उन्हें ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ा। यह अपील एक दशक से अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रही। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री सिंह और अन्य को अब क्लीन चिट दिए जाने संबंधी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं। अपीलकर्ता के निधन के कारण यह अपील निष्फल मानकर समाप्त की जाती है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गृहमंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया गया

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गृहमंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होने गृहमंत्री शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गृहमंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होने गृहमंत्री शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होने सदन में गृहमंत्री के उपस्थित नहीं होने पर सवाल उठाए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है। इसके दो ही संभावित कारण हो सकते हैं। या तो गृह मंत्री ने गोलीबारी का आदेश दिया, या उन्हें गोलीबारी की जानकारी नहीं थी। पहले मामले में, वे दोषी हैं। दूसरे मामले में, वे अक्षम हैं। तीसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। अगर गृह मंत्री को गोलीबारी की जानकारी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि वे अक्षम हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। यह तर्क की सीधी सी बात है। साथ ही, वे सदन में नहीं आए हैं। वे क्यों नहीं आ रहे हैं? वे भारत के बहादुर गृह मंत्री माने जाते हैं। अगर उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया, तो उन्हें आकर स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया। वैसे भी, बड़ा मुद्दा यह है कि मुझे संसद में बोलने का अधिकार है, और मुझे उस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लोकसभा में अपने भाषण पर लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में वह क्यों नहीं आ रहे? देश के तथाकथित बहादुर गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं हैं? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया और कोई आदेश जारी नहीं किया, तो उन्हें बस यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उन्होंने आदेश जारी नहीं किया। लोकसभा में अपने भाषण के बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, दो संभावित स्थितियां हो सकती हैं। एक यह कि गृह मंत्री ने आदेश जारी किया। दूसरी यह कि गृह मंत्री को गोलीबारी की जानकारी नहीं थी। पहले मामले में, वे दोषी हैं, दूसरे में, वे अक्षम हैं इन दोनों में से एक होना ही चाहिए, कोई तीसरी संभावना नहीं है। अगर गृह मंत्री को गोलीबारी की जानकारी भी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि वे अक्षम हैं; अन्यथा, अगर उन्होंने आदेश दिया, तो वे दोषी हैं।

दिल्ली पुलिस के प्रवेश और पूर्व जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष को गिरफ्तार करने के प्रयास का विरोध

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

29 जुलाई राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण करीब 40 मिनट के लिए दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कार्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आइशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आइशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। ब्रिटास ने पुलिस कार्रवाई को हाल के छात्र प्रदर्शनों से जोड़ते हुए कहा कि आइशी घोष की एकमात्र गलती यह थी कि उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कोई भी छात्र यदि सक्रिय राजनीति या आंदोलनों में शामिल होता है तो उसे इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नड्डा ने कहा कि वह भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, आपातकाल के दौरान मुझे कक्षा से भी गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि ऐसा दो बार हुआ था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने-अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया।

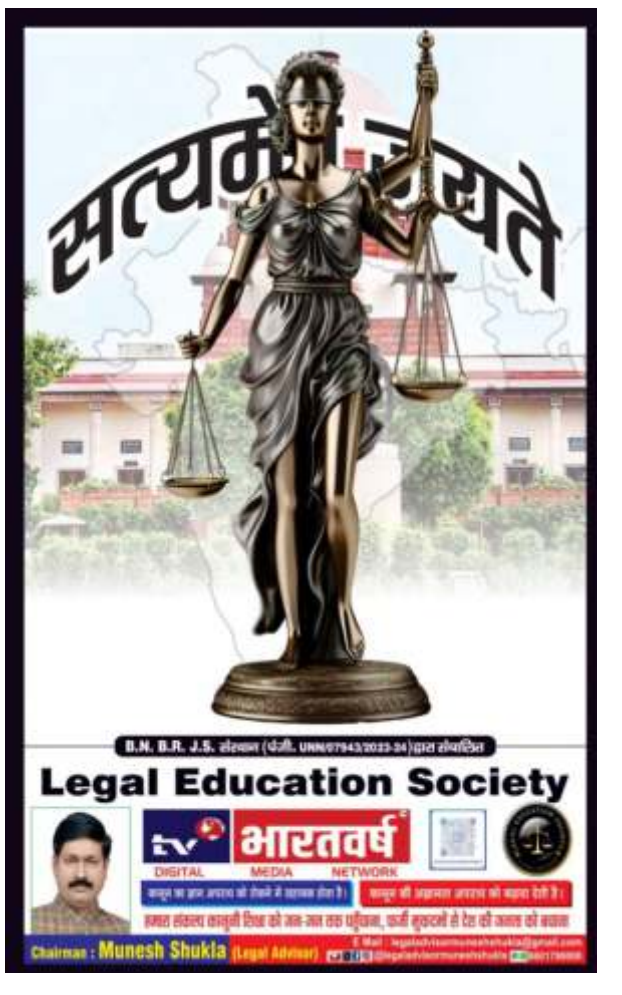

जापान में करियर का सुनहरा मौका भारतीय ग्रेजुएट्स के लिए खुला JET प्रोग्राम

जापान एक पॉपुलर देश बन चुका है, जहां पर भारतीय वर्कर्स काम करना पसंद करते हैं। यहां पर कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, जिनके जरिए भारतीय ग्रेजुएट्स जापान जाकर अपना करियर बना सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। क्या आप जापान में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर है। जापान में करियर बनाने के लिए JET (जापान एक्सचेंज एंड टीचिंग) प्रोग्राम एक शानदार ऑप्शन है। इसके जरिए भारतीय ग्रेजुएट्स जापान जा सकते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए जापान में रहने और काम करने का अवसर मिलता है। इसके साथ-साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को बढ़ावा भी दिया जाता है। जापान की सरकार 1987 से ही JET प्रोग्राम चला रही है। इसके तहत युवाओं को स्कूलों में असिस्टेंट लैंग्वेज टीचर्स (ALTs) और स्थानीय सरकारी कार्यालयों में कोऑर्डिनेटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस (CIRs) के तौर पर काम करने का मौका मिलता है। JET प्रोग्राम का मकसद युवाओं को जापान के अलग-अलग इलाकों में भेजकर जमीनी स्तर पर इंटरनेशनल समझ को मजबूत करना है। आइए JET प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानते हैं। हाल ही में भारत में स्थित जापानी दूतावास ने 2026 JET प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीयों को जापान विदा किया। इसमें 22 असिस्टेंट लैंग्वेज टीचर्स (ALTs) और 4 कोऑर्डिनेटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस (CIRs) शामिल हैं। मौजूदा वक्त में लगभग 1000 लोकल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन (कॉन्ट्रैक्टिंग संगठन) JET प्रोग्राम के तहत चुने गए लोगों को नौकरी देते हैं। इसमें 46 प्रांत और 18 नामित शहर भी शामिल हैं। JET प्रोग्राम के तहत चुने गए शख्स को क्या काम करना है, इसका फैसला हर एक प्रांत के गवर्नर या शहर-कस्बे के मेयर द्वारा लिया जाता है। हालांकि, प्रोग्राम से जुड़े संगठन मुख्य तौर पर स्थानीय सरकारी प्राधिकरण होते हैं। अगर किसी को प्राइवेट स्कूलों में भी JET प्रोग्राम के तहत चुने गए लोगों की जरूरत होती है, तो उन्हें वहां पर भी तैनात किया जा सकता है। JET प्रोग्राम के लिए सिर्फ वही शख्स अप्लाई कर सकता है, जिसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसे साबित करने के लिए भारतीय पासपोर्ट देखा जाता है।

आवेदक को जापान को लेकर दिलचस्पी होनी चाहिए। वह विदेश में रहने के लिए तैयार हो और उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतरीन होनी चाहिए।

ALT पदों के लिए जापानी भाषा जानना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर जापानी आती है तो प्राथमिकता मिल सकती है।

CIR पदों के लिए जापानी भाषा आना जरूरी है, जो आमतौर पर जापानी लैंग्वेज प्रोफिसिएंसी टेस्ट (JLPT) N2 के बराबर होती है। असिस्टेंट लैंग्वेज टीचर्स (ALTs) को जापान के प्राइमरी, जूनियर हाई और सीनियर हाई स्कूलों में जापानी टीचर्स के साथ मिलकर काम करना होगा। उनका काम स्टूडेंट्स की अंग्रेजी सुधारने में मदद करना है। इसके साथ-साथ उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भी रूबरू करवाना है। कोऑर्डिनेटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस (CIRs) के तौर पर काम करने वाले शख्स को स्थानीय सरकारों को अनुवाद, इंटरप्रिटेशन, अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज प्रोग्राम और पर्यटन से जुड़े कामों में मदद करना होगा। यहां क्लिक कर आप इस पूरे प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं।

एडमिशन नहीं मिलने के बाद स्टूडेंट के इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया

साइट हैक हो गई है। मुझे बस एक मौका चाहिए।' आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलने के बाद स्टूडेंट के इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया। IIT कानपुर की वेबसाइट पर यह मैसेज देखने के बाद संस्थान में हड़कंप मच गया। स्टूडेंट के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात होने लगी। तब आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल को स्टूडेंट का टैलेंट भी नजर आया। इसके बाद जो हुआ उसकी काफी चर्चा हो रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, एक स्टूडेंट ने कुछ हफ्ते पहले आईआईटी कानपुर के के नए शुरू हुए 'बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी' प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। स्टूडेंट की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की माने तो उसने एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लिया था, तय फीस जमा कर दी थी, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे और अपने साइबर सिक्योरिटी स्किल्स के प्रूफ भी जमा कर दिए थे। फिर भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा रहे हैकथॉन में शामिल होने का मौका भी नहीं दिया गया था। इसके बाद स्टूडेंट ने जो किया वह चर्चा का विषय बन गया। कहा जा रहा है कि आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलने के बाद स्टूडेंट ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की वेबसाइट हैक करने का दावा किया। स्टूडेंट ने वेबसाइट हैक करके मैसेज छोड़ा, 'Site is hacked. All I need is just a fair chance.' संस्थानों को जब वेबसाइट हैक होने की भनक लगी तो कानूनी कार्रवाई की बात उठने लगी।

वैभव 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 48वीं रैंकिंग पर पहुंच गए

जस्टिन ग्रीव्स ने शानदार गेंदबाजी से रिकॉर्ड बनाया मेडन ओवर डालते हुए पांच विकेट अपने नाम किए

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला है। वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी जस्टिन ग्रीव्स ने अपनी शानदार गेंदबाजी से ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। उन्होंने लगातार पांच मेडन ओवर डालते हुए पांच विकेट अपने नाम किए और रिकॉर्ड युग में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए।

मौजूद जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय जस्टिन ग्रीव्स ने मुकाबले के तीसरे दिन 27 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। यह उनके टेस्ट करियर का पहला पांच विकेट लेने का कारनामा भी है। उनकी घातक गेंदबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के इस मुकाबले में मजबूत स्थिति बना ली है। गौरतलब है कि इससे पहले लगातार चार मेडन ओवर में विकेट लेने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम था। उन्होंने वर्ष 2016 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। अब जस्टिन ग्रीव्स ने लगातार पांच मेडन ओवर में विकेट लेकर उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि यह जस्टिन ग्रीव्स का 17वां टेस्ट मैच है। उन्होंने अपने करियर में पहली बार एक पारी में पांच विकेट लेने का मुकाम हासिल किया। पाकिस्तान की पहली पारी 282 रन पर सिमट गई, जबकि वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 311 रन बनाए थे। इस तरह मेजबान टीम को पहली पारी के आधार पर 29 रन की बढ़त मिली। मुकाबले के दौरान एक समय पाकिस्तान की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही थी। टीम ने तीन विकेट पर 244 रन बना लिए थे और कप्तान शान मसूद शानदार शतक पूरा कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पहली पारी में बड़ी बढ़त हासिल कर लेगा, लेकिन इसके बाद जस्टिन ग्रीव्स ने मैच का पूरा रुख बदल दिया।

इंग्लैंड के क्लब क्रिकेट में क्लिकी पोंटिंग विवाद से मचा बवाल

क्रिकेट में गेंदबाजों की अपील, बल्लेबाजों की चालाकी और फील्डरों की चतुराई अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन इंग्लैंड के क्लब क्रिकेट से सामने आया एक मामला हर किसी को हैरान कर रहा है। यहां एक खिलाड़ी पर आरोप लगा है कि उसने बल्लेबाज के बल्ले से गेंद लगने का भ्रम पैदा करने के लिए चुटकी बजाने की आवाज निकाली, ताकि अंपायर उसे आउट दे दें। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब यह मामला क्लिकी पोंटिंग के नाम से वायरल हो गया है। यह विवाद 25 जुलाई 2026 को इंग्लैंड की नॉर्थ यॉर्कशायर एंड साउथ डरहम क्रिकेट लीग के डिवीजन-2 मुकाबले से जुड़ा है। आरोप है कि सॉल्टबर्न क्रिकेट क्लब के फील्डर ब्रायन डिवाइन ने गेंद के बल्ले के पास से गुजरते समय चुटकी बजाई। उसी दौरान विकेटकीपर ने कैच लपक लिया और ऐसा लगा जैसे गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई हो। लोकल लीग के मैचों में DRS या स्निकोमीटर जैसी तकनीक मौजूद नहीं होती। ऐसे में अंपायर अपने देखने और सुनने के आधार पर फैसला लेते हैं। आरोप है कि चुटकी बजाने की आवाज ने बल्ले से एज लगने का भ्रम पैदा किया, जिससे अंपायर प्रभावित हो सकते थे। ये मामला सामने आने के बाद नॉर्थ यॉर्कशायर एंड साउथ डरहम क्रिकेट लीग ने इसकी औपचारिक जांच शुरू कर दी है। लीग ने बयान जारी कर कहा कि 25 जुलाई के डिवीजन-2 मैच से जुड़ी शिकायत मिली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने तक इस पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की जाएगी।

शुभमन गिल ने एक बार फिर नंबर-1 बल्लेबाज का ताज हासिल कर लिया

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज का ताज एक बार फिर से हासिल कर लिया है। वहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी ने टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 230 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर 48वां स्थान हासिल कर लिया है। शुभमन गिल अपने करियर में तीसरी बार वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचे हैं।न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरिल मिचेल वेस्टइंडीज सीरीज में नहीं खेल रहे थे, जिसका फायदा शुभमन गिल को मिला और वे मिचेल को पछाड़कर दोबारा वनडे के शीर्ष बल्लेबाज बन गए हैं। मिचेल इस साल जनवरी से नंबर-1 की कुर्सी पर काबिज थे। वहीं, टी20 रैंकिंग की बात करें तो भारत के ईशान किशन 910 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। ईशान किशन ने हाल ही में 916 रेटिंग अंक हासिल किए थे, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में अभिषेक शर्मा (931) और डेविड मलान (919) के बाद तीसरी सबसे बड़ी रेटिंग है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 151 रन बनाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी 230 पायदान चढ़कर सीधे 48वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा दो स्थान के सुधार के साथ T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में छठे स्थान पर आ गए हैं, जबकि श्रेयस अय्यर सात पायदान की छलांग लगाकर 24वें स्थान पर पहुंचे हैं। गेंदबाजों में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई 31 स्थानों के सुधार के साथ T20I गेंदबाजी रैंकिंग में 41वें नंबर पर आ गए हैं। चोट के कारण जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहने वाले वरुण चक्रवर्ती तीन स्थान खिसकने के बावजूद अभी भी टॉप-10 गेंदबाजों में बने हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 21 स्थानों की छलांग लगाकर 48वां स्थान हासिल किया है।

सरकार ने शुरू की खास स्कीम

अब दुबई ट्रिप के लिए मिलेंगे 75 हजार रुपये

कुछ महीने पहले तक दुबई दुनिया के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में गिना जा रहा था. साल 2025 में यहां करीब 1.96 करोड़ विदेशी पर्यटक पहुंचे थे, जो अब तक का रिकॉर्ड था.

लेकिन ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद मध्य पूर्व में बढ़े तनाव का असर दुबई के पर्यटन पर भी पड़ा. पर्यटकों की संख्या तेजी से घटी और अब उन्हें वापस लाने के लिए दुबई सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है.

इस योजना के तहत यूएई में रहने वाले लोग अगर अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को दुबई घूमने के लिए बुलाते हैं, तो उन्हें करीब 75 हजार रुपये (3,000 दिरहम) तक के रिवॉर्ड मिल सकते हैं.

जेल प्रशासन ने दिया शालीन जवाब

होटल की जगह जेल में कर दी बुकिंग

फिलीपींस के ब्यूरो ऑफ जेल मैनेजमेंट एंड पेनोलॉजी (BJMP) की आधिकारिक फेसबुक पोस्ट के मुताबिक, वीकेंड ट्रिप के लिए होटल ढूंढ रही एक महिला से ऐसी गलती हो गई कि उसने होटल की जगह महिलाओं की जेल में ही कमरा बुक करने का मैसेज भेज दिया. जेल प्रशासन ने जब सच्चाई बताई तो महिला ने तुरंत माफी मांग ली. बाद में महिला की अनुमति से पूरी बातचीत सोशल मीडिया पर साझा की गई, जो अब तेजी से वायरल हो रही है. बीजेएमपी के मुताबिक, महिला फिलीपींस के बागियो शहर घूमने की योजना बना रही थी. ठहरने के लिए होटल तलाशते समय उसने सोशल मीडिया पर बीजेएमपी बागियो

सिटी जेल फीमेल डॉमिटरी का पेज खोल लिया. उसे लगा कि यह किसी होटल का पेज है.महिला ने मैसेज भेजकर पूछा कि क्या वीकेंड के लिए कोई कमरा उपलब्ध है. महिला का मैसेज पढ़ने के बाद जेल स्टाफ ने बेहद विनम्रता से जवाब दिया.मैडम, यह महिलाओं की जेल है.इतना पढ़ते ही महिला को अपनी गलती का एहसास हो गया. उसने तुरंत सिर्फ 'सॉरी' लिखकर जवाब दिया.

कोई एसी सैलून में इस सुख का आनंद लेता है, तो कोई गली के कोने वाली दुकान या पेड़ की छांव में बैठे बार्बर के हाथों का कमाल

के एक पुरुषों के सैलून में पहुंच गईं और करीब 1 डॉलर (करीब 85 रुपये) में फेस मसाज करवा डाली. अब उनका यही अनुभव सोशल

आईने के सामने उनके साथ सेल्फी लेने लगता है, तो बाकी ग्राहक भी उत्सुकता से पूरा नजारा देखते रहते हैं.

पोस्ट में भारत को सुरक्षित जगह भी बताया है और यहां के लोगों की मेहमाननवाजी की तारीफ की है.

देखकर उन्हें 'कल्चर शॉक' लगा और उनका मानना है कि भारत भी अपने पड़ोसी देश से कई बातें सीख सकता है.

टेक की नौकरी छोड़ क्रिएटर बना कपल

35 लाख रुपये सालाना की टेक नौकरी छोड़ने वाले एक कपल का दावा है कि उन्होंने कंटेंट क्रिएशन से तीन साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने अपनी कमाई, ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरे इनकम सोर्स का पूरा हिसाब बताया.

सोशल मीडिया पर अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई कितनी होती है. अब एक कपल ने इस सवाल का जवाब अपनी पूरी इनकम डिटेल्स के साथ दिया है.

टेक सेक्टर की लाखों रुपये की नौकरी छोड़ने वाले इस कपल का दावा है कि उन्होंने कंटेंट क्रिएशन से तीन साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. मुस्कान मित्तल और आशीष गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी टेक जॉब से लेकर फुल-टाइम कंटेंट क्रिएटर बनने तक का सफर बताया.

उनका कहना है कि पिछले तीन साल में हजारों लोगों ने उनसे पूछा कि वे ट्रैवल और कंटेंट क्रिएशन का खर्च कैसे उठाते हैं. इसी वजह से उन्होंने पहली बार अपनी कमाई का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया. वीडियो में आशीष गुप्ता ने बताया कि कंटेंट क्रिएशन शुरू करने से पहले वह डेटा एनालिस्ट थे और उनकी इन-हैंड सैलरी करीब 12 लाख रुपये सालाना थी.

वहीं मुस्कान मित्तल सॉफ्टवेयर डेवलपर थीं और उन्हें करीब 23 लाख रुपये सालाना मिलते थे. यानी दोनों की संयुक्त सालाना आय करीब 35 लाख रुपये थी. ऐसे

वीडियो हो रहा वायरल

मुस्कान और आशीष का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूजर्स उनकी पारदर्शिता की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कंटेंट क्रिएशन में इतनी सफलता हर किसी को नहीं मिलती. फिलहाल, कपल की ओर से साझा किए गए इनकम के आंकड़ों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं हुआ है.

हुई कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत कपल के मुताबिक, मई 2023 में उन्होंने ट्रैवल से जुड़े वीडियो बनाना शुरू किया. वियतनाम ट्रिप का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे 20 हजार से ज्यादा व्यूज मिले. इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से ट्रैवल, रिलेशनशिप और हेल्थ से जुड़ा कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया.

करीब एक दशक से चल रही कानूनी लड़ाई अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. अमेरिकी हेल्थकेयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन (जेएंडजे) ने घोषणा की है कि वह अपने बेबी पाउडर और अन्य टैल्क उत्पादों को लेकर दायर हजारों मुकदमों के निपटारे के लिए 5.5 अरब डॉलर (करीब 52 हजार करोड़ रुपये) का भुगतान करेगी. हालांकि, सबसे अहम बात यह है कि कंपनी ने यह नहीं माना है कि उसके टैल्क उत्पादों से कैंसर होता है. जेएंडजे का कहना है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं.

67 साल के हुए संजय दत्त: संघर्ष, विवाद और शानदार वापसी से बने बॉलीवुड के 'बाबा'

बॉलीवुड के दमदार अभिनेता संजय दत्त आज, 29 जुलाई को अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए और करोड़ों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। हालांकि उनकी जिंदगी जितनी सफल रही, उतनी ही संघर्षों और विवादों से भी भरी रही। नशे की लत, कानूनी मुश्किलें और व्यक्तिगत दुखों का सामना करने के बावजूद उन्होंने हर बार मजबूत वापसी कर यह साबित किया कि मुश्किलें इंसान को रोक नहीं स क तीं।

संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को अभिनेता सुनील दत्त और हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री नरगिस के घर हुआ। फिल्मी माहौल में पले-बढ़े संजय ने बचपन में ही अपने पिता की फिल्म 'रेशमा और शेरा' में एक छोटे से किरदार के जरिए पर्दे पर कदम रखा। इसके बाद साल 1981 में फिल्म 'रॉकी' से उन्होंने बतौर हीरो बॉलीवुड में एंट्री की। लेकिन फिल्म की रिलीज से ठीक तीन दिन पहले उनकी मां नरगिस का निधन हो गया, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया।मां के निधन के गहरे सदमे ने संजय को नशे की ओर धकेल दिया। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि परिवार को उनकी जिंदगी की चिंता सताने लगी। आखिरकार पिता सुनील दत्त उन्हें इलाज के लिए अमेरिका के एक रिहैब सेंटर ले गए। वहां से लौटने के बाद संजय ने खुद को संभाला और पूरी मेहनत के साथ अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया।इसके बाद संजय दत्त ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में अभिनय कर अपनी अलग पहचान बनाई। 'साजन', 'सड़क', 'खलनायक', 'वास्तव', 'मुन्ना भाई एमबीबीएस', 'लगे रहो मुन्ना भाई', 'धमाल', 'परिणीता', 'अग्निपथ', 'पीके', 'केजीएफ: चैप्टर 2', 'लियो' और हालिया फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' सहित कई फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने सराहा। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और संवाद अदायगी ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल कर दिया।आज संजय दत्त केवल एक सफल अभिनेता ही नहीं, बल्कि संघर्षों से लड़कर आगे बढ़ने की मिसाल भी माने जाते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी कठिन दौर से बाहर निकला जा सकता है।

एंटी पेपर लीक बिल पर मायावती का सवाल, बोलीं- सिर्फ सख्त कानून नहीं, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार भी जरूरी

मायावती ने संसद में हुई बहस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर अधिकांश राजनीतिक दल गंभीर चर्चा करने के बजाय एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में अधिक व्यस्त दिखाई दिए। उनके अनुसार, यदि सरकार वास्तव में पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान चाहती है तो नए कानून के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधार, परीक्षा प्रबंधन को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने जैसे ठोस कदम भी उठाने होंगे।

लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। हंगामे के बाद ध्वनि मत से मंजूरी मिल गई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि देश में पेपर लीक के जघन्य अपराध और उसके कारण नौजवान छात्र-छात्राओं का उनका भविष्य अंधकार होता देख अनेक आत्महत्या जैसी अति-दुखद घटनाओं की रोकथाम की उपाय के रूप में संसद ने एक बार फिर से एक और सख्त सजा के प्रावधान वाला कानून बनाने वाला बिल लोकसभा में आज अन्ततः पास कर दिया है, लेकिन क्या केवल इससे समस्या का समाधान हो जाएगा, इसकी चिंता लोगों में बरकरार है, क्योंकि लोगों को यह आपाधापी-जल्दबाज़ी में लिया गया एक और कदम ज़्यादा लगता है, जबकि अन्य और भी उपायों को तत्काल सख़्ती से लागू करना जरूरी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि वास्तव में यह कदम भी पेपर लीक होने के बाद सख़्त सज़ा का प्रावधान करता है, जबकि पेपर लीक का पूरा मामला इस महा अपराध को होने देने से पहले ही इसे रोकने का है, अर्थात अपराध नियंत्रण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि अधिकतर मामलों में यहां कहीं भी प्रभावी होता हुआ नजर नहीं आता है, और यह पेपर लीक के पिछले क़ानून के निष्प्रभावी होने से भी स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हकीकत में अन्य अपराधों की तरह पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध के नियंत्रण के लिए सख़्त से सख़्त कानून से अधिक इसकी रोकथाम के लिए बेहतर से बेहतर उपाय करने की ज़रूरत है, जिसके तहत शिक्षा के लिए शोषणकारी ऋण को सस्ता करके उसे कल्याणकारी बनाना, सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा आदि सहित पूरी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है, ताकि गरीबों, उपेक्षितों, शोषितों और अन्य मेहनतकश लोगों के बच्चे भी समता व समानता के साथ आगे बढ़ सकें, जो परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के कल्याणकारी संविधान का उद्देश्य तो है, किन्तु इसका हर स्तर पर वर्तमान में घोर अभाव है। दरअसल, अमीर परिवारों के लोग तो धनबल के आधार पर अपनी मनमानी व मनचाही पढ़ाई आदि प्राप्त कर लेते हैं, किन्तु करोड़ों ग़रीब परिवारों के बच्चे-बच्चियों का क्या जो होनहार होने के बावजूद अपना जीवन संवार नहीं पाते हैं। वैसे भी पेपर लीक शिक्षा व्यवस्था में बिगाड़ का केवल एक उदाहरण है, जबकि शिक्षा व्यवस्था में बिगाड़ की जड़ काफी गहरी व अति-गंभीर है। इसके निदान के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति व नेक नीयत के साथ अनवरत ईमानदार प्रयास की ज़रूरत है, तभी कुछ मुट्ठी भर लोगों के बजाय करीब 140 करोड़ लोगों का यह देश आगे बढ़ पाएगा। यह अति-दुखद है कि पेपर लीक रोकथाम संबंधी बिल पर भी बहस के दौरान अधिकतर पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पायीं अर्थात् संसद में चर्चा के दौरान पूरी गंभीरता कम व एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप ही ज़्यादा रहा। ऐसे में क्या नया बनने वाला यह पेपर लीक निरोधक क़ानून कितना सार्थक होगा, इससे लोगों का शंकित होना उचित है। ऐसे में मूल प्रश्न यही है कि क़ानून पर क़ानून क्या इस जटिल समस्या का सही समाधान कर पाएगा? सरकार इसके अलावा भी अन्य बेहतर उपायों पर भी ज़रूर विचार करे तो यह देश के उज्जवल भविष्य के लिये बेहतर होगा।

बदमाशों ने महिला पर हमला किया और 15 लाख रुपये के गहने तथा नकदी लूटकर फरार

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में पीजीआई क्षेत्र के वृंदावन सेक्टर-दो में बुधवार दोपहर बेख़ौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक मकान में घुसकर महिला पर हमला किया। करीब 15 लाख रुपये के जेवर तथा 20 हजार रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना के समय घर में महिला अकेली थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। ओपी चौधरी अस्पताल में सुपरवाइजर लक्ष्मीकांत मिश्रा की पत्नी बाजार गई थीं, जबकि बेटा और बेटी ड्यूटी पर थे। घर की पहली मंजिल पर उनकी बहू ज्योति मिश्रा अकेली थीं। दोपहर करीब दो बजे उन्हें दूसरे कमरे से आवाज सुनाई दी। जांच करने पहुंचीं तो बदमाश घर में घुस चुके थे। विरोध करने पर बदमाशों ने लोहे की बट जैसे हथियार से उनके सिर पर हमला कर दिया। दोबारा वार होने पर वह बेहोश हो गईं, जिसके बाद आरोपी जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। शाम करीब चार बजे ड्यूटी से लौटी ननद आकांक्षा ने घर का सामान बिखरा और ज्योति को बेहोश देखा। सूचना पर एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव और पीजीआई इंस्पेक्टर सुनील सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि बदमाश जल्दबाजी में घर का टीवी और 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक मौके पर ही छोड़कर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में दिनदहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर अकेली महिला पर हमला किया और करीब 15 लाख रुपये के गहने तथा नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना की जांच जारी है।

PM पोषण योजना में बड़ा बदलाव, अब बच्चों को हर शुक्रवार मिलेगा हलवा, रसोइयों को भी राहत

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम पोषण योजना (मिड-डे मील) को और प्रभावी बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। अब सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हर शुक्रवार सूजी का हलवा परोसा जाएगा। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों (कुक-कम-हेल्पर) को भी बड़ी राहत मिली है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में हुई मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की प्रबंधकारिणी बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पीएम पोषण योजना में नया बदलाव किया है। इसके तहत अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार स्कूलों में सूजी का हलवा परोसा जाएगा। कुल 14 शुक्रवार के दौरान बच्चों को हलवा मिलेगा, जिसमें 7 शुक्रवार मीठा सूजी का हलवा और 7 शुक्रवार नमकीन सूजी का हलवा परोसा जाएगा। हलवा बनाने के लिए रसोइयों को प्रति छात्र प्रति कार्य दिवस 2 रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होगी। साथ ही यह व्यवस्था भी लागू होगी कि यदि किसी रसोइए की आयु शैक्षणिक सत्र के बीच पूरी हो जाती है, तो वह सत्र समाप्त होने तक अपनी सेवाएं जारी रख सकेगा। नए रसोइयों का चयन अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले किया जाएगा। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के तहत कार्यरत सिस्टम एनालिस्ट, मंडल एवं जिला समन्वयक और कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है। इन कर्मचारियों के मानदेय में वर्ष 2016 के बाद पहली

बार वृद्धि की गई है। बैठक में संविदा पर कार्यरत सिस्टम एनालिस्ट, समन्वयक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य कर्मचारियों के लिए अधिकतम कार्य आयु 60 वर्ष निर्धारित करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा मध्याह्न भोजन प्राधिकरण में सहायक निदेशक के चार पदों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से नियुक्ति का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत आठ नए निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। करीब 15.08 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाली इन परियोजनाओं में नमकीन, ब्रेड, रस्क, सोया उत्पाद, पास्ता, पोल्ट्री फीड और अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के साथ रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

छह लाख करोड़ की परियोजनाओं के लिए जल्द होगा भूमि पूजन

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार अगले भूमि पूजन समारोह को अब तक का सबसे बड़ा निवेश आयोजन बनाने की तैयारी में है। औद्योगिक विकास विभाग और इन्वेस्ट यूपी की समीक्षा बैठकों में बताया गया कि लगभग छह लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाएं भूमि पूजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके साथ ही निवेश की रफ्तार बनाए रखने के लिए सभी विभागों को 10 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्ताव जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। विभागवार प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है और विशेष रूप से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नई कंपनियों को आकर्षित करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार अगले तीन माह में 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली 50 बड़ी औद्योगिक इकाइयों और 100 करोड़ रुपये की लागत वाली 500 मध्यम परियोजनाओं को प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे करीब एक लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। निवेश परियोजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। वर्ष 2023 और 2024 में कुल 45 एलओसी जारी किए गए थे, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 70 एलओसी जारी हो चुके हैं। अब प्रत्येक माह 15 नई कंपनियों को एलओसी जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। वर्ष 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेश में हजारों निवेश परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ और उनके क्रियान्वयन की रफ्तार बढ़ी है। सरकार अब इसी गति को अगले चरण तक ले जाने की तैयारी कर रही है।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेशी नागरिकों के आधार कार्ड ,मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार कर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली समेत अन्य विदेशी नागरिकों के आधार कार्ड बनवाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सद्दाम पुत्र अलाउद्दीन के रूप में हुई है, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। एटीएस के अनुसार, इससे पहले इस गिरोह से जुड़े 17 आरोपियों को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार से गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया था कि गिरोह वीपीएन (VPN) के जरिए सिस्टम का रिमोट एक्सेस लेकर अवैध तरीके से आधार कार्ड तैयार करता था। इसके लिए जन्म प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और स्कूल प्रमाणपत्र जैसे फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार किए जाते थे। गिरोह अपने सदस्यों के नाम पर लॉगिन आईडी बनवाकर उनका दुरुपयोग भी करता था। एटीएस ने आरोपी सद्दाम को 28 जुलाई 2026 को मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से गिरफ्तार किया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस अब अदालत से कस्टडी रिमांड लेकर आरोपी से गहन पूछताछ करेगी, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला आयोजित, छात्रों को ऑनलाइन ठगी से बचाव के दिए गए टिप्स

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में बुधवार दोपहर को एसपी जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में किंगसन इंटर कॉलेज में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ को बढ़ते साइबर अपराधों, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। इस कार्यशाला में साइबर पुलिस टीम ने आधुनिक साइबर अपराधों से बचाव के व्यावहारिक तरीके बताए और शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी नगर विनी सिंह, थाना साइबर पुलिस टीम और सदर कोतवाली की साइबर हेल्पडेस्क टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि वर्तमान समय में ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग जैसे साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। कार्यशाला के दौरान आरक्षी शमसुद्दीन ने विद्यार्थियों को "साइबर अरेस्ट" जैसे नए साइबर अपराधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से डराने-धमकाने का प्रयास करे और पैसे की मांग करे, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को देनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया का जिम्मेदारी और सावधानी से उपयोग करने की भी सलाह दी। सदर कोतवाली की साइबर एक्सपर्ट सोनिया शर्मा ने संदिग्ध एपीके फाइलों, अनजान लिंक और फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन से होने वाले खतरों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या अविश्वसनीय स्रोत से ऐप डाउनलोड करने से मोबाइल और बैंकिंग संबंधी जानकारी चोरी हो सकती है। उन्होंने मजबूत पासवर्ड, दो-स्तरीय सुरक्षा (टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन) और साइबर हेल्पलाइन का उपयोग करने की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्नोत्तरी सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे और विशेषज्ञों से उनके जवाब प्राप्त किए। इससे विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रभारी परिवार परामर्श समिति के डॉ. आशीष श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

उन्नाव: चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन कटी, आईसीयू में भर्ती; प्रतिबंध के बावजूद बिक्री पर उठे सवाल

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की वजह से एक और गंभीर हादसा हो गया। बुधवार शाम 6 बजे हरदोई पुल पर बाइक से गुजर रहे एक युवक की गर्दन चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से उसे निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और आईसीयू में इलाज चल रहा है। सदर कोतवाली पुलिस के अनुसार, हरदोई पुल पर बाइक सवार युवक की गर्दन मांझे से कटने की सूचना मिली थी। घायल की पहचान शहर के कल्याणी देवी मोहल्ला निवासी 42 वर्षीय सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद रजा के रूप में हुई है। बताया गया कि वह बाइक से हरदोई पुल पार कर रहे थे, तभी सड़क पर फैले प्रतिबंधित चाइनीज मांझे में उनकी गर्दन उलझ गई और गहरा घाव हो गया। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद राहगीर आकाश यादव ने तुरंत बाइक रुकवाई और गंभीर रूप से घायल सिराज अहमद को दरोगा बाग स्थित आशा अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। डॉक्टरों के अनुसार गर्दन पर गहरा घाव होने के कारण उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। इस हादसे के बाद शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री और उसके इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की रोक के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझा आसानी से उपलब्ध है, जिसके कारण आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं।

कंगना रनौत के बयान के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, फूंका पुतला

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के मोहान कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मधु रावत के नेतृत्व में कंगना रनौत का पुतला फूंका गया। यह प्रदर्शन कंगना रनौत द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले युवक-युवतियों पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में किया गया। मधु रावत ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले युवाओं का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि कंगना रनौत अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। रावत ने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी जाती है, तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मधु रावत के साथ महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष लखनऊ मीना रावत, कन्हैया कुरील, हुब्लाल, हर्षित, नयन, मोतीलाल कन्नौजिया, सुबराती, कमल किशोर, चांद बाबू और गोला रावत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

उन्नाव: गुरु पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को उन्नाव जनपद के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अलसुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा-अर्चना के लिए घाटों पर पहुंचने लगे। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए थे। एनडीआरएफ, जल पुलिस, गोताखोरों, मजिस्ट्रेटों और पुलिस बल की तैनाती के साथ पूरे आयोजन पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु सुबह करीब चार बजे से ही गंगा तटों पर पहुंचने लगे। गंगा बैराज, शुक्लागंज गंगाघाट, बक्सर घाट और फतेहपुर चौरासी सहित जिले के प्रमुख घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। स्नान के बाद लोगों ने अपने गुरु का पूजन कर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों ने श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए थे। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी, होमगार्ड और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई, ताकि श्रद्धालु गहरे पानी की ओर न जा सकें। एनडीआरएफ, जल पुलिस और गोताखोर लगातार घाटों पर निगरानी करते रहे। कुछ स्थानों पर भीड़ बढ़ने से हल्की अफरा-तफरी की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस और प्रशासन की तत्परता से स्थिति तुरंत सामान्य कर दी गई। किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए प्रशासन ने सभी प्रमुख घाटों पर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की। कंट्रोल रूम से वरिष्ठ अधिकारी लगातार फुटेज पर नजर बनाए रहे, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की ओर से गंगा घाटों पर विशेष आरती, भजन-कीर्तन और प्रवचन का आयोजन किया गया। संत-महात्माओं ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। कई स्थानों पर भंडारे आयोजित किए गए, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा विवाद TMC प्रिंट गद्दे सप्लाई करने वाली फर्म पर गिरी गाज

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

चार दिन पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में जोड़ों को उपहार स्वरूप टीएमसी झंडे प्रिंट कवर वाले गद्दे देने वाली अलीगढ़ की फर्म के 68.85 लाख रुपये के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। फर्म को काली सूची में डालने के साथ अनुबंध भी खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 24 जुलाई को हड़हा स्थित डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। इसमें 459 जोड़े विवाह बंधन में बंधे थे। जोड़ों को उपहार में गद्दे दिए गए थे। उनमें कई गद्दों के कवर का रंग हरा, केसरिया व सफेद था, साथ ही उसमें फूल बने हुए थे। गद्दों में अंग्रेजी में टीएमसी भी लिखा हुआ था। यह बंगाल की टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) पार्टी के झंडे के हूबहू जैसा था। मामले में सामान सप्लाई करने वाली अलीगढ़ के बरौली रोड पटवारी का नगर निकट पुलिस चौकी की फर्म मेसर्स इंडियन जनरल ट्रेडर्स ने 15 हजार रुपये में शासन से निर्धारित 22 सामानों को डालने का ठेका लिया था जबकि निर्धारित दर 21 हजार रुपये प्रति जोड़ा था। कम दर पर टेंडर डालने से उसे सप्लाई की जिम्मेदारी मिली थी। इस हिसाब से फर्म का 68.85 लाख रुपये का भुगतान बना है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सेवा में कमी के कारण फर्म को भुगतान नहीं किया जाएगा। समाज कल्याण अधिकारी श्रीप्रकाश पांडेय का कहना है कि फर्म काली सूची में डाली जाएगी। इसके साथ ही अनुबंध भी खत्म किया जाएगा, जिससे भविष्य में फर्म कोई काम नहीं कर पाएगी। यह सभी कार्रवाई प्रस्तावित हैं। इसके लिए फर्म को जारी नोटिस के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

उन्नाव: गंगाघाट पुलिस ने साइबर ठगी की शिकार महिला के ₹7,490 कराए वापस

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गंगाघाट पुलिस ने एक पीड़िता को राहत दिलाई है। पुलिस ने यूपीआई धोखाधड़ी के शिकार आसमा फारुकी के ₹7,490 वापस कराए हैं। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन में की गई। त्रिभुवन खेड़ा निवासी आसमा फारुकी पत्नी सानू ने 14 जनवरी 2026 को ऑनलाइन साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि यूपीआई के माध्यम से उनके खाते से ₹7,490 की धोखाधड़ी की गई है। शिकायत मिलने के बाद थाना गंगाघाट की साइबर टीम ने मामले की जांच शुरू की। टीम ने संबंधित बैंक और तकनीकी माध्यमों से समन्वय स्थापित किया। लगातार प्रयासों के बाद बुधवार, 29 जुलाई 2026 को ठगी गई पूरी धनराशि ₹7,490 पीड़िता के बैंक खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गई। अपनी राशि वापस मिलने पर पीड़िता ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह, अपराध निरीक्षक माबूद रजा और महिला आरक्षी समरीन बानो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

CEO से पहले सचिव बने जगदीश आफले सचिव के साथ बैंक खातों के संचालन की भी मिलेगी कमान

राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ट्रस्ट ने जगदीश आफले को सचिव और बैंक खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। उनकी नियुक्ति पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में औपचारिक मुहर लगने की संभावना है।

राम मंदिर में दान चोरी के मामले के बाद ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति से पहले सचिव पद पर नियुक्ति करने का फैसला लिया है। इस जिम्मेदारी के लिए जगदीश आफले को चुना गया है। ट्रस्ट की ओर से उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा 2 सितंबर को होने वाली बैठक में की जाएगी। सिर्फ सचिव ही नहीं, उन्हें ट्रस्ट के बैंक खातों के संचालन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (S B I) में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) भी बनाया गया है। ऐसे में उनकी भूमिका अब मंदिर के प्रशासनिक और वित्तीय दोनों कामकाज में अहम मानी जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे निवासी जगदीश आफले पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने आईआईटी मुंबई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम किया। यूरोप और अमेरिका की कंपनियों में भी उन्होंने लंबे समय तक सेवाएं दीं। सेवानिवृत्ति के बाद जब राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उन्होंने अपने पेशेवर अनुभव को मंदिर निर्माण परियोजना के लिए समर्पित कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने बिना वेतन परियोजना प्रबंधक (Project Manager) के रूप में जिम्मेदारी संभाली और निर्माण कार्य की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जगदीश आफले बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे हैं। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद संघ की ओर से उन्हें परियोजना प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। तभी से वह अयोध्या में रहकर मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों का संचालन कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने पहले ही CEO, सचिव और प्रवक्ता जैसे नए प्रशासनिक पद बनाने का फैसला किया था। हालांकि CEO की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है। ट्रस्ट के अनुसार, CEO पद के लिए करीब 5,200 आवेदन आए हैं। इनकी जांच और चयन की प्रक्रिया सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली समिति कर रही है। चूंकि इस प्रक्रिया में समय लगना तय है, इसलिए प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए पहले सचिव की नियुक्ति कर दी गई। पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के पद छोड़ने के बाद ट्रस्ट के बैंक खातों के संचालन को लेकर नई व्यवस्था बनाने की जरूरत पड़ी थी। इसी के तहत ट्रस्ट ने जगदीश आफले को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाने का प्रस्ताव भारतीय स्टेट बैंक को भेजा। शुरुआती स्तर पर कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के कारण खाते के संचालन में देरी हुई, लेकिन बाद में ट्रस्ट की ओर से नया प्रस्ताव भेजे जाने के बाद बैंक ने इसे मंजूरी दे दी। अब ट्रस्ट के खातों का संचालन सामान्य रूप से शुरू हो चुका है। हाल ही में राम मंदिर में दान राशि की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठे। इसके बाद प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए। सचिव पद का सृजन और नियुक्ति भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले समय में ट्रस्ट प्रवक्ता की नियुक्ति भी करेगा, ताकि आधिकारिक जानकारी एक तय व्यवस्था के तहत सार्वजनिक की जा सके। 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में जगदीश आफले की नियुक्ति पर औपचारिक मुहर लगने की संभावना है। इसके बाद वह सचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। वहीं CEO और प्रवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी

झांसी में एक भीषण सड़क दुर्घटना की घटना सामने आई,15 से 20 यात्री घायल

उत्तर प्रदेश के झांसी में एक भीषण सड़क दुर्घटना की घटना सामने आई है, जिसमें मंगलवार देर रात झांसी-कानपुर हाईवे पर प्रयागराज से मध्य-प्रदेश के विदिशा जा रही एक स्लीपर बस पारीछा पावर प्लांट के सामने हाईवे पर खड़े ट्रक से जा टकराई। इस भीषण हादसे ने जहां पूरी तरह से अफरा-तफरी मचा दी तो वहीं ड्राइवर और एक यात्री की मौत भी हो गई है। इसके अलावा बस में सवार 15 से 20 यात्री घायल हुए। हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस ड्राइवर टक्कर होने के बाद स्टेयरिंग में बुरी तरह से फंस गया था, जिसमें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकालकर सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। झांसी में यह दर्दनाक हादसा बड़ागांव क्षेत्र में झांसी-कानपुर हाईवे पर पारीछा पावर प्लांट के सामने हुआ। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से मध्य-प्रदेश के विदिशा जा रही स्लीपर बस अचानक खराब खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक स्टेयरिंग में फंस गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही थाना बड़ागांव पुलिस और कई एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे चालक को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और सभी घायलों को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा। प्रयागराज से मध्य-प्रदेश के विदिशा जा रही स्लीपर बस को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें सवार अधिकांश यात्री मध्य-प्रदेश के रहने वाले हैं, जो प्रयागराज में अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद गंगा में अस्थि एवं फूल प्रवाहित कर वापस विदिशा लौट रहे थे।

अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने बड़ा ऐलान किया

सावन महीने की शुरूआत इस बार 30 जुलाई से हो रही है, जिसमें कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ियों को लेकर सुरक्षा के काफी इंतजाम किए हैं। अब मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान का सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें शादाब ने कहा है कि आस्था के लिए संविधान में सभी को समान अधिकार है, सड़क पर 5 मिनट नमाज पढ़ने में दिक्कत है, जबकि कांवड़ यात्रा के दौरान 15 दिन के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं और आम लोगों को असुविधाओं सहन करनी पड़ती है। अब उनके इस बयान को लेकर खिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान का कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए वीडियो के बाद अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने बड़ा ऐलान किया है कि वह 30 जुलाई से कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों जांच का अभियान चलायेंगे। संगठन के पदाधिकारी सचिन सिरोही का कहना है कि जांच अभियान के दौरान दुकानदारों की पहचान और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मेरठ से हरिद्वार तक कांवड़ मार्ग पर कोई मुस्लिम भोजनालय अपनी पहचान छिपाकर संचालित होता मिलेगा तो उसके खिलाफ पुलिस- प्रशासन से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग करेंगे। हिन्दूवादी संगठन द्वारा AIMIM के नेता शादाब चौहान द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई। संगठन ने आरोप लगाया कि ऐसे बयान करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले हैं और शादाब चौहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी सचिन सिरोही का कहना है कि कांवड़ यात्रा हिंदू समाज की वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा और आस्था का प्रतीक है।

प्रोफेसर पर उनकी पत्नी अन्वेष्णा ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई

आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर निशीथ श्रीवास्तव पर उनकी पत्नी अन्वेष्णा ने घरेलू हिंसा, दूसरी महिलाओं से संबंध और वैवाहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। एसीपी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि कल्याणपुर थाने में दर्ज एफआईआर में सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता डिपार्टमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वहीं, प्रोफेसर निशीथ श्रीवास्तव ने सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। एफआईआर के अनुसार, आईआईटी कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर अन्वेष्णा श्रीवास्तव की शादी दिसंबर 2012 में हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं। छोटा बेटे साढ़े छह साल का है। आरोप लगाया गया है कि 2025 से पति-पत्नी के संबंधों में तनाव आ गया। दिसंबर-2025 में प्रोफेसर निशीथ ने पत्नी के सामने कबूला कि 2022 में उन्होंने अपनी एक विवाहित पीएचडी छात्रा के साथ अपने ही ऑफिस में 4 बार शारीरिक संबंध बनाए थे। आरोप है कि नवंबर-2025 से निशीथ एक महिला प्रोफेसर से अनुचित संबंधों में हैं। अन्वेषणा का आरोप है कि विरोध करने पर पति ने सहनशीलता बढ़ाने के लिए कहा। आरोप है कि 11 नवंबर 2025 को प्रोफेसर निशीथ ने घर में तोड़फोड़ की। खौलती चाय फेंकी और शादी की तस्वीरें हथौड़ा मारकर तोड़ दी। चाकू दिखाकर डराया। वहीं, 15 जनवरी 2026 को कथित तौर पर जमीन पर पटककर चेहरे और सिर पर कई थप्पड़ मारे, जिससे काफी चोटें आईं। यह सब कुछ मासूम बेटे के सामने हुआ। जब संस्थान के सिक्योरिटी गार्ड आए तो प्रोफेसर ने बताया कि पत्नी ने थप्पड़ मारे, लेकिन बच्चे ने सच बता दिया। 30 अप्रैल 2026 को मानसिक तनाव के कारण अन्वेषणा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 4 जुलाई 2026 प्रोफेसर ने पत्नी की इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। रिश्तेदारों के साथ अभद्रता, घर में घुसने से रोकने और घर में सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी का भी आरोप लगाया गया है।